उद्योगों के लिए आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकीय उन्नयन को प्रोत्साहन देने के प्रयोजन से एक प्रौद्योगिकीय उन्नयन निधि योजना (टी.यू.एफ.एस.) शुरू करने का निर्णय लिया है ताकि उनकी उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाया जा सके। इस योजना के अंतर्गत परिधान क्षेत्र सहित अभिज्ञात किए गए वस्त्र और पटसन क्षेत्र के पात्र एकक मनोनीत नोडिए अभिकरणों से ब्याज की लागू दर पर ऋण के लिए आवेदन कर सकेंगे जो अर्थक्षमता आदि के संबंध में स्वत: संतुष्ट होने पर आवेदक एकक को ऋण के पुनर्भुगतान करने आदि की शर्तों को तय करके ऋण प्रदान करेंगी। प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना को 1 अप्रैल, 1999 से स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस योजना के अंतर्गत वस्त्र मंत्रालय द्वारा ऋणदात्री नोडिए एजेंसियों (आई.डी.बी.आई., सिडबी और आई.एफ.सी.आई.) को 5% के ब्याज बिंदु तक के ब्याज की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

(ख) प्रतियोगी कीमतों पर अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता के फैब्रिकों की घरेलू उपलब्धता के साथ-साथ अन्य संबद्ध मुद्दों को सुनिश्चित करने की आवश्यकता को मान्यता देते हुए कच्चे माल की सुगम उपलब्धता तथा प्रौद्योगिकी, वित्तीय प्रोत्साहन, प्रक्रियाओं को सरल बनाने, बाजार संवर्धन, कोटा संबंधित मुद्दों, आदि से संबंधित सुझाव प्राप्त हुए हैं। इन सुझावों और उद्योग के समग्र हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ऐसे निर्यात को सुकर बनाने के लिए समय-समय पर कदम उठा रही है जिनमें क्रेता-विक्रेता बैठकों, मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए निर्यातकों को प्रोत्साहन देना, निर्यात उत्पादन के लिए रियायती शुल्क पर पूंजीगत माल के आयात का अधिकार देना, निर्यात उत्पादन के लिए कच्चे माल के शुल्क मुक्त आयात के लिए विशेष प्रबंध करना, परिधान क्षेत्र में मानव संसाधन विकास का संवर्धन करना आदि शामिल हैं।

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान हमारे परिधानों के निर्यात निम्नानुसार थे:-

वर्ष	अमरीकी मिलियन डालर में मूल्य
1996-97	4,762.10
1997-98	4,910.70

(घ) वर्ष 1997-98 के दौरान भारत के कुल निर्यात में हस्तशिल्प, पटसन और कयर सहित वस्त्र निर्यातों का अंशदान लगभग 36.5% है।

वस्त्र उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन

2474. श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में बदलती हुई परिस्थितियों को देखते हुए वर्तमान वस्त्र उत्पादन प्रणाली में व्यापक परिवर्तन लाने की आवश्यकता है;

(ख) क्या सरकार ने वर्तमान परिस्थितियों के संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(ग) यदि हां, तो कतिपय परिवर्तनों हेतु प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन प्रस्तावों के कार्यान्वयन के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): (क) से (घ) वस्त्र मंत्रालय द्वारा उद्योग के प्रतिनिधियों को भी शामिल करते हुए 24 जुलाई, 1998 के अपने संकल्प द्वारा श्री एस.आर. सत्यम की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित की है जो कि अन्य बातों के साथ-साथ उत्पादन प्रौद्योगिकियों, डिजाईन, विपणन कौशल तथा आसूचना प्रौद्योगिकी सहित वस्त्र क्षेत्र के समस्त क्रियाकलापों में मानव संसाधनों का विकास करने के लिए एक गहन नीति तथा रणनीति बनाएगी। यह समिति अपनी रिपोर्ट शीघ्र ही प्रस्तुत करेगी।

Percentage of textile production

2475. SHRI GOPALSINH G. SOLANKI: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) the State-wise percentage of textile production in the Country during the last five years;

(b) the details of its demand and supply, in comparison to its production, State-wise; and

(c) what was the position by the end of 1998?

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI KASHIRAM RANA): (a) The State-wise percentage of cloth produced in the cotton/man-made fibre textile mills during the last five years is given below:—

States/Union Territory	1993-94 (%)	1994-95 (%)	1995-96 (%)	1996-97 (%)	1997-98 (%)
Andhra Pradesh	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00
Assam	0.00	0.00	0.01	0.14	0.24
Delhi	0.05	0.06	0.04	0.02	0.00
Gujarat	25.18	24.87	26.14	26.20	27.52
Haryana	0.32	0.42	0.35	0.03	0.11
Karnataka	2.63	2.86	2.45	2.36	2.01

Kerala	0.93	0.98	1.22	0.92	0.99
Madhya Pradesh	3.82	3.35	2.94	1.63	1.81
Maharashtra	44.94	44.09	43.86	45.34	42.64
Orissa	1.43	1.54	1.30	1.33	1.15
Punjab	2.15	2.29	2.95	3.60	3.48
Rajasthan	2.12	2.76	3.32	3.53	4.12
Tamil Nadu	8.84	10.19	9.27	8.65	9.22
Uttar Pradesh	2.19	2.11	1.70	1.42	2.40
West Bengal	2.58	2.43	2.44	1.88	1.66
Pondicherry	2.79	2.04	2.02	2.96	2.65

(b) and (c) There is no restriction on the movement of textile items between one state to another. The total production of cloth and yarn is showing steady increase during the last five years. Even though population is constantly increasing the per capita availability of cloth is showing steady increase during the last five years as given below:—

Year	Per capital availability of cloth(in Sq. mtrs)
1993-94	26.22
1994-95	25.98
1995-96	27.99
1996-97	29.30
1997-98	30.92

The present capacity and production is sufficient to meet the demand for yarn and cloth in the country. The state-wise percentage of cloth produced in the mill sector during April to December, 1998 is given below:—

States/UnionTerritories	Percentage Share
Assam	0.24
Gujarat	25.70
Haryana	0.45
Karnataka	1.19
Kerala	0.74
Madhya Pradesh	1.74
Maharashtra	45.71
Orissa	1.17
Punjab	3.66
Rajasthan	3.94
Tamil Nadu	8.92
Uttar Pradesh	2.68
West Bengal	1.39
Union Territory	
Pondicherry	2.47

Janata Cloth Scheme

2476. DR. C. NARAYANA REDDY: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Janata Cloth Scheme, which was introduced with the objective to provide sustained income to handloom weavers, has been totally phased out;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) what steps have been taken by Government to provide adequate protection and support to unskilled handloom weavers?

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI KASHIRAM RANA): (a) and (b) Yes, Sir. A committee constituted in 1991 to review the Janata Cloth Scheme recommended its phasing out, since it had contributed to the de-skilling of the weavers.

It was decided by the Government to introduce a modified Janata Cloth Scheme w.e.f. 1993-94 for the 8th Plan period. The Scheme was however, extended during 1997-98 to facilitate transition.

(c) Consequent to phasing out of the Janata Cloth Scheme by the end of the 8th Plan period, the Government introduced two major developmental schemes. Viz., the Project Package Scheme (PPS) during 1991-92 and Handloom Development Centre (HDC) Scheme during 1993-94, to provide financial support to weavers in a integrated and coordinated manner which also included skill upgradation of de-skilled handloom weavers.

हथकरघा बुनकरों को वित्तीय सहायता दिया जाना

2477. श्रीमती सरोज दुबे: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में कपड़ा मिलों की संख्या में वृद्धि होने के कारण हथकरघा बुनकरों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन हथकरघा बुनकरों को प्रोत्साहित करने तथा उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु सरकार के पास कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): (क) से (ग) देश में कपड़ा मिलों की संख्या में वृद्धि होने के कारण हथकरघा बुनकरों की आर्थिक स्थिति खराब नहीं हुई है। यद्धपि,